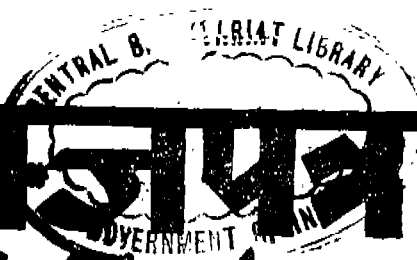




भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 19, 1996 (आश्विन 27, 1918)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 19, 1996 (ASVINA 27, 1918)

इस भाग में निम्न सूची संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संग्रहण के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

केनरा बैंक

कार्मिक प्रबंधन अन्भाग, कार्मिक विभाग

बंगलूर-560002, दिनांक 13 सितम्बर 1996

सं. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पट्टल धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक की निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व गंजूरी से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

संक्षिप्त नाम और आरम्भ :

(1) ये विनियम केनरा बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1966 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्वयता एतत् रूप से उपबंधित होगा, जो विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

1-289GI/96

(5475)

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् भूल विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

4. (1) 1-11-1987 के तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने गिनिविष्ट वेतनमान लागू होंगे।

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 6400-150-7000

वेतनमान 6 रु. 5950-150-6550

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 5350-150-5950

वेतनमान 4 रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 3 रु. 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान 2 रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 1 रु. 2100-120-4020

4(2) 1-7-93 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) दीर्घ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

वेतनमान 6 रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 10450-250-11450

वेतनमान 4 रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 3 रु. 8050-230-9200-250-9700

वेतनमान 2 रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 1 रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4.3 उप विनियम (1) और (2) की क्रिमी वात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रहना अपेक्षित है।

3. मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

5.1 विनियम 4(2) के उपबंधों के अधधीन, दिनांक 1-11-1992 को या उसके बाद से वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित उप संख्याओं के अधधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4 के उपबन्धित विभिन्न वेतनमानों में वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मजूरी के अधधीन वार्षिक आधार पर प्रयोज्य होंगी और वे जिस महीने में बचे होंगी वह उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(ख) वेतनमान 1 तथा 2 के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुँचने के लिए एक वर्ष के पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(या) सहित आगे की वेतनवृद्धियाँ केवल सीके (ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के विशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षता-रोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 तथा 3 के अधिकतम पर पहुँचने वाले अधिकारियों को यथास्थिति वेतनमान 2 तथा 3 के अंतिम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(या) दी जाएगी/जाएगी। वेतनमान 2 के अंतिम प्रक्रम पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले

में रु. 230/- की अधिक से अधिक की वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी तथा वेतनमान 3 के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परन्तु 1-11-1994 और उसके बाद से, मूल वेतनमान 3 के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान 3 में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियाँ पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान 2 तथा 3 के ही विशेषाधिकार, परिलक्ष्यता, जगह, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

2. नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आई आई बी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आई आई बी) परीक्षा का भाग 1 या भाग 2 उत्तीर्ण कर लिया है, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों सभाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

स्पष्टीकरण 2

(क) 1-11-1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने वाले अथवा पहुँच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मागीनवर्षों के अधीन, यदि कोई हो, सी ए आई आई बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों को स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भरा दिया जाएगा।

जिनमें से सी०ए०आई०आई०बी० के का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है

1. एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे।

जिनमें से सी०ए०आई०आई०बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिये हैं

2. एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे।

3. दो वर्ष पश्चात् रु० 250/- प्रति माह जिसमें से रु० 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे।

(ख) 1-11-1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होंगे पर, व्यवसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पनरीकृत रहेंगी :

जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	1. वेतनमान के अधिकतम पहुँचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह।
जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिये हैं	2. वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह।
	3. वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर दो वर्ष पश्चात् रु० 300/- प्रति माह।

वेतनवृद्धि घटक	1-11-1993 को महंगाई भत्ता	जहाँ बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ वेतन कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
रु०	रु०	रु०
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

परन्तु विनियम 5(3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग 1 या 2 के लिए व्यवसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे।

टिप्पणी :

(1) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यवसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका स्वतन्त्र निर्धारित करने समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आई आई बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उत्तिरिक्त वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियों उपलब्ध नहीं है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के पदज में व्यवसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा।

(2) 1-11-1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्यवसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

3. क जो अधिकारी 1-11-1993 को बैंक की स्थाई सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 1-11-1993 को परीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थाईकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ख. जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच चुका है या जो 1-11-1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) प्राप्त कर चुका है वह 1-11-1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अग्रिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 1-11-1993 को दिये महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा। यहाँ नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अधिवर्षिता दिया जाएगा।

टिप्पणी : 1. ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को दिये होंगे जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

2. मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क) + (ख) + संवृद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

3. नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में दिये व्यवसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा।

4. नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में दिये व्यवसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा।

5. नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि के अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

ग. जिस अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमाणा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी।

4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

21 (1) 1-11-1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी :—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रामिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960—100 की निमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदिये होगा।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदिये होगा :—

(1) रुपए 2500 तक वेतन का 0.67% धन (+)

(2) रुपए 2500 से ऊपर परन्तु रुपए 4000 तक वेतन का 0.55% का धन (+)

(3) रुपए 4000 से ऊपर परन्तु रुपए 4260 तक वेतन का 0.33% धन (+)

(4) रुपए 4260 से ऊपर वेतन का 0.17%

21. 21-7-1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :—

- (1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सागान्य आधार 1960—100 की विमाही औसत से 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।
- (2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :—
 - (क) रुपए 4800/- तक वेतन का 0.35% धन (+)
 - (ख) रुपए 4800/- से ऊपर परन्तु रुपए 7700/- तक वेतन का 0.29% का धन (+)
 - (ग) रुपए 7700/- से ऊपर परन्तु रुपए 8200/- तक वेतन का 0.17% धन (+)
 - (घ) रुपए 8200/- से ऊपर वेतन का 0.09%

टिप्पणी : 1. महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

2. महंगाई भत्ते को लिए व्यवसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से गिना जाएगा।

5. मूल विनियमों में, विनियम 22 के उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

22 (1) 1-11-1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मकान किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

22 (2) 1-11-1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :—

स्तंभ I	स्तंभ II
कार्यस्थान निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
1. सरकार के प्राधिकरणों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 13% प्रति माह
2. क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा "बी" के परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 12% प्रति माह
3. क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा वंचनायित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10-1/2% प्रति माह
4. क्षेत्र III	वेतन का 9-1/2% प्रति माह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है

उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ 2 के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150% जो भी कम हो, होगा।

टिप्पणी : 1. मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा 1-7-1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

2. मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यवसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से प्रभावी गिना जाएगा।

6. मूल विनियमों में, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

23 (1) 1-11-1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्राधिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :—

स्थान	दर
क. क्षेत्र I के स्थान और गांव राज्य	मूल वेतन का 4-1/2%— अधिकतम रु० 335/- प्रति माह
ख. 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 3-1/2%— अधिकतम रु० 230/- प्रति माह

7. मूल विनियमों में, विनियम 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

24 (1) अधिकारी अपने परिवार के लिए दिए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय

1-11-1994 और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अधधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और बाबा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :—

श्रेणी	वार्षिक
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु० 1500/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु० 2000/-

टिप्पणी : उपयोग में न आई चिकित्सा महापिता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

2. चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दी जायेगी, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के "परिवार" में उसका पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित सन्तान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

ख. अस्पताल में भर्ती खर्च :—

- 1-1-1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक को खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अधधीन चिकित्सक, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथा-स्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धार्मिक संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उसके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी।
- 1-11-1994 को या उसके बाद से, मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कैंसर, ध्वंस्त्रस्तना, थैलसिमिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदयरोग, कृच्छ्र रोग, गुर्दे की बीमारी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारी, मनादिकार दोष और मधुमेह।

टिप्पणी : वरालु उपचार के मामले में दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी। यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा।

2. उक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल हैं) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल हैं) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक मंडल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें अनाथ रखने का विनिश्चय कर सकता है और

यदि निदेशक मंडल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल हैं) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं धर्तियों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

3. चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निम्नलिखित अधिकारियों को भी दी जाएगी।

8. मूल विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किन्तु यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1-11-1994 को और उसके बाद से अपने वृत्तमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परन्तु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वृत्तमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

9. मूल विनियमों में, विनियम 41 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

41(4) 1-6-1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वृत्तमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तदनुकूली दरों में विराम भत्ता पाने का हकदार होगा।

दैनिक भत्ता (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वृत्तमान	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4
वृत्तमान iv और उससे ऊपर के अधिकारी	250	200	175
वृत्तमान I/II/III के अधिकारी	200	175	150

परन्तु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटों से कम किन्तु 4 घंटों से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता दिये जायेंगे।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वृत्तमानों के अधिकारियों के होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रकारों तक सीमित होगी।

आन-पान खर्च (रुपये)				
अधिकारियों की श्रेणी/वर्तमान	ठहरने की पावना	प्रमुख "ग" वर्ग के नगर	अव I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वर्तमान VI	4* होटल	250	200	175
और VII				
वर्तमान IV	3* होटल	250	200	175
और V				
वर्तमान II	2* होटल	200	175	150
और III				
वर्तमान I	1* होटल	200	175	150
		(अवातानुकूलित)		
		(अवातानुकूलित)		

(ग) निवेशक मंडल, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार उत्तर प्रावधान (ख) में निर्धारित सीमा के परे अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति का निर्धारण कर सकता है।

(घ) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर परन्तु (ख) में निर्धारित सीमाओं में अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

(ङ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जायेगा।

(च) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा नि:शुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जायेगा।

(छ) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जायेगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किये बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(ज) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय में बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

विराम भत्तों की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अभिप्राय है, 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुँचने के वास्तविक समय तक की जायेगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटों से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटों से कम न हो।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के उप-विनियम 2 (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

42.2(1) 1-7-1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरण अधिकारी को गालगाड़ी से अपने सामान को परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :

वैतन सीमा	परिवार-सहित	परिवार-रहित
रु. 4250 से	3000 किलोग्राम	1000 किलोग्राम
रु. 6210 प्रति माह		
रु. 6211 प्रति माह और उससे अधिक	पूरा माल बिन्दा	2000 किलोग्राम

11. मूल विनियमों में, विनियम 45 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

45. भविष्य निधि और पेंशन :

1. प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आवद्ध होने के लिए सहमत होगा।

2. भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1-11-1993 को और उसके बाद से क. पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वैतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जायेगा।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किये गये अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वैतन 10% की दर से किया जायेगा।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किये गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।

3. 29-9-1995 का या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे।

(क) जो अधिकारी 29-9-1995 के पूर्व बैंक की सेवा में थे, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो।

(ख) जो अधिकारी 29-9-1995 का या उसकी बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भरती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी :

भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु "वैतन" का अर्थ है मूल वैतन, जिसमें अवकाश वेतनवृद्धियाँ, स्थानांतरण भत्ता व्यवसायिक अहंता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्तों का वेतनवृद्धि घटका शामिल है।

12. मूल विनियमों में विनियम 46 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

46. उपदान

1. प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :

(क) सेवा-निवृत्ति पर

(ख) मृत्यु पर

(ग) ऐसी निःशुल्कता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है।

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर या।

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा समाप्त की जाकर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्त पर।

2. अधिकारी को दिये उपदान की राशि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा

के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से उतिरित राशि का पात्र होगा।

परन्तु अधिकारी की सेवाओं 1-7-1993 से 31-10-1994 के दौरान समाप्त हो गई हैं और उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन में तात्पर्य दिनिशम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।

टिप्पणी

यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छः माहों या उससे अधिक की कोई अवधि दक्षता है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जायेगा।

नोट टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किये गये संशोधन अधिसूचना से 15 दिनांक 14 अप्रैल 1990 द्वारा गजट किये गए थे।

CANARA BANK
PERSONNEL MANAGEMENT SECTION
PERSONNEL WING

Bangalore-560 002, the 13th September 1996

No. ————In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act) 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations namely:—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (1) These Regulations may be called Canara Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 1996.
- (2) Save as otherwise expressly provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979 hereinafter referred to as Principal Regulation, for Regulation 4, the following may be substituted, namely:

4(1) On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

- (a) Top Executive Grade:
Scale VII Rs. 6400-150-7000.
Scale VI Rs. 5950-150-6550.
- (b) Senior Management Grade:
Scale V Rs. 5350-150-5950.
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350.
- (c) Middle Management Grade:
Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910.
Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390.
- (d) Junior Management Grade:
Scale I Rs. 2100-120-4020

4(2) On and from 01-07-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under:

- (a) Top Executive Grade:
Scale VII Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000.
Scale VI Rs. 11450-300-12650,

(b) Senior Management Grade:

Scale V Rs. 10450-250-11450.

Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450.

(c) Middle Management Grade:

Scale III Rs. 8050-230-9200-250-9700.

Scale II Rs. 6210-230-8740.

(d) Junior Management Grade:

Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050.

4(3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5, the following may be substituted, namely:

5(1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 01-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses:—

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.
- (b) Officers in Scale-I and Scale-II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.
- (c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the scale III or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale-II and one such increment of Rs. 250/- for Officers in the last stage of Scale-III.

Provided that on and from 01-11-1994 Officers in substantive Scale-III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale-III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

NOTE: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

EXPLANATION-I:

In the case of an Officer who has passed Part-I or Part-II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an Officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said examination.

EXPLANATION II:

(a) On and from 01-11-1987, Officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIB Examination as under:

Those who have passed only Part-I of CAIB	(i)	Rs. 100/- p. m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of CAIB	(i)	Rs. 100/- p. m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii)	Rs. 250/- p. m. after two years of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits

(b) On and from 01-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under:

Those who have passed only Part I of CAIB	(i)	Rs. 120/- p. m. after one year on reaching top of the scale
Those who have passed both Parts of CAIB	(i)	Rs. 120/- p. m. after one year on reaching top of the scale
	(ii)	Rs. 300/- p. m. after two years on reaching top of the scale

Provided that Officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part-I and II as the case may be.

NOTE:

(i) If an Officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the Officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 01-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All Officers who are in the Bank's permanent service as on 1st November 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

NOTE:

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An Officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus Dearness Allowance payable thereon as on 1st November 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service:

Increment component	DA as on 01-11-1993	Total FPA payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

NOTE:

(i) F.P.A. as indicated in (c) above shall be payable to those Officer employees who are provided with Bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for Officers eligible for HRA shall be (A)+(B)+HRA drawn by the concerned Officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An Officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

4. In principal Regulations, for Regulation 21, the following may be substituted, namely:

21(1) On and from 01-11-1987, Dearness Allowance scheme shall be as under:

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:

- (i) 0.67% of 'pay' up to Rs. 2500/-, plus,
- (ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,
- (iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,
- (iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

21(2) On and from 01-07-1993, Dearness Allowance scheme shall be as under:

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1950=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:

- (i) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4800/-, plus
- (ii) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/- plus,

(iii) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/- plus,

(iv) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200/-.

NOTE :

(i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance with effect from 01-11-1994.

5. In principal Regulations, for Sub-regulation (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely :

22(1) Where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, on and from 01-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from 01-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area-I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area-II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10.5% of the pay p.m.
(iv) Area-III	9.5% of the pay p.m.

Provided that if an Officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the HRA payable as per Column II above, whichever is lower.

NOTE :

(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 01-07-93.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 01-11-1994.

6. In principal Regulations, for Sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted, namely :

23(i) On and from 01-11-1993, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place shall be payable.

Places (1)	Rates (2)
(a) Places in Area-I and in the State of Goa	4.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- p.m.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State capitals and Chandigarh, Pondichery and Port-Blair not covered by (a) above.	3.5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- p.m.

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely :

24(1) An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :

(a) Medical Expenses :

On and from 01-11-1994 reimbursement of medical expenses to an Officer in the grade specified in Column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the Officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof :

TABLE	
Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1,500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2,000/-

Note :

(i) An Officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December 1994.

Explanation :

'Family' of an Officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 01-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an Officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The Officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an Officer and 75% in the case of his family members :

Cancer, Leukaemia, Thalassemia, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

Note: The cost of medicines etc., in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in Sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all Officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).

(3) Medical aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the Officers who are placed under suspension.

8. In principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely:

25. No Officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the Officer on and from 01-11-1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an Officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the Officer.

9. In principal Regulations, for sub-Regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely:—

41(4) On and from 01-06-1995 an Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:

Grades/Scales of Officers	Daily allowances (Rupees)		
	Major 'A' class cities	Area-I	Other places
Officers in Scale-IV & above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale-I/II/III	200.00	175.00	150.00

provided that:

- Where the total period of absence is less than 3 hours but more than 4 hours, Halting allowance at half the above rates shall be payable.
- Officers in various grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room

accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below:

Grades/Scales of Officers	Eligibility to stay	Boarding Charge (Rupees)		
		Major 'A' class cities	Area-I	Other places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel	200.00	175.00	150.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

- The board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.
- Where lodging is provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.
- Where boarding is provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.
- Where lodging and boarding are provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.
- A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all Inspecting Officers.

Explanation:

For the purpose of computing Halting Allowance per diem shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, per diem shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-Regulation 2(i) of Regulation 42, the following may be substituted, namely:—

42. (2) (i) On and from 1-7-1993 an Officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits:

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

11. In principal Regulations, for Regulation 45, the following may be substituted, namely:

45. Provident Fund and Pension

(1) Every Officer shall become a member of the provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(1) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993 :

- (a) in case of an Officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the Officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

- (b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the Officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of Provident Fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(3) Officers joining the bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of Officers shall not be covered by the Pension Scheme :

- (a) an Officer who was in service of the bank prior to 29-9-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.
- (b) an Officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note :

'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation increments, Officialing Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. Gratuity :

(1) Every Officer, shall be eligible for gratuity on :

- (a) retirement
- (b) death
- (c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical Officer approved by the Bank;
- (d) resignation after completing ten years of continuous service; or
- (e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of gratuity payable to an Officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months pay.

Provided that where an Officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an Officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Note : If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata the period.

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above regulations were Gazetted vide Notification No. 15 dated 14th April 1990.

M. V. KAMATH
General Manager

प्रसम्भक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन निबन्धक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996

